65

संख्या– 179 /XV-2/01(02)/2009

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–02

देहरादूनः दिनांक 28 मार्च, 2014:

विषय– वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान संख्या–28 आयोजनागत (सामान्य) अन्तर्गत 10–दुग्धशाला का सुदृढीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1372–73/लेखा–दुग्धशाला का सु0यो0 पत्रा0/2013–14, दिनांक 06 दिसम्बर, 2013 एवं पत्र संख्या–940–41/लेखा–दुग्धशाला का सु0 पत्रा0/2013–14, दिनांक 13 सितम्बर, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दुग्धशाला का सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु निम्नानुसार ₹ 25.37 लाख की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹ 25.37 लाख निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कर व्यय हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क.सं0	विवरण	संख्या	प्रस्तावित धनराशि (लाख रू0 में)
	प्लाण्ट एवं मशीनरी		
1.	आटोमैटिक दही मेकिंग यूनिट स्थापना	01	16.07
2.	डीजल जनरेटर सेट स्थापना	01	7.70
3.	ऑफ लाइन क्रीम सेपरेटर क्षमता 1000 ली0	01	1.60
	योग–		**25.37**

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
2. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
3. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
4. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
5. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
6. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219 (2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

कमशः2

7. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
8. उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों एवं शासन के वर्तमान मितव्ययता संबंधी आदेशों के अन्तर्गत ही किया जाय।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कार्य उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुमोदित निर्माण एजेन्सी द्वारा करवाया जायेगा साथ ही धनराशि का आहरण कर सम्बन्धित जनपदीय दुग्ध संघ को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2014 तक पूर्व उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
11. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाय जिसके लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद से किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास-00-आयोजनागत-102-डेरी विकास परियोजनायें-10-दुग्धशाला का सुदृढ़ीकरण-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-284/XXVII(i)/2013, दिनांक 30 मार्च, 2013 एवं शासनादेश दिनांक 10 जून, 2013 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(डॉ0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-149(1)/XV-2/2014तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ अफसर-प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, दुग्ध को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल)/पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार सिंह)
अनु सचिव।